

विचार-मंथन

भारत के कई राज्यों के युवा नशे की लत के शिकार होते चले जा रहे हैं। किसी समय पंजाब ड्रग्स का केंद्र माना जाता था लेकिन अब यह समस्या पूरे देश में फैल चुकी है। तो यह सवाल बिल्कुल सঠज है कि इस समस्या से निपटें कैसे? तमाम तरह की कोशिशों हो रही हैं और इन्हें में से एक बिल्कुल नई कोशिश हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुई है। वहां हर थाने के माध्यम से ऐसे किट वितरित किए जा रहे हैं जिस किट पर मूत्र की एक बूंद यदि डाली जाए तो पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति ने किस तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। निश्चय ही जिन घरों के युवा ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं, उन युवाओं के बारे में परिवार को यह किट सतर्क करेगी। दरअसल न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि हर पहाड़ी राज्य में व्यापक पैमाने पर नशे का नेटवर्क बन चुका है। वैसे ड्रग्स तस्करो के असली शिकार तो वहां तफरीह के लिए पहुंचने वाले पर्यटक होते हैं लेकिन इस चक्र में स्थानीय युवाओं का नेटवर्क तैयार

किया जाता है जो खुद इसका शिकार हो जाते हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि जिन युवाओं को अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ना था वे किसी काम के नहीं रह जाते हैं। निजी तौर पर युवक और उसके परिवार को तो नुकसान होता ही है, समाज भी पीछे चला जाता है। इसका असर राष्ट्र पर भी होता है क्योंकि युवा ही तो देश के आधार स्तंभ हैं। नशे के कुछ सीढ़ागर भले ही पैसा कमाने के लिए ड्रग्स के कारोबार को बढ़ाते हैं लेकिन बहुत बड़ी सच्चाई यह भी है कि भारत में ड्रग्स के कारोबार के दो प्रमुख सहयोगी हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा चीन। अभी जो मणिपुर भीषण जातीय संघर्ष से गुजर रहा है, वहां कुछ-कुछ दिनों के अंतराल पर ड्रग्स के खेप भी कहां से बरामद हो रहे हैं? यह सत्य किसी से छिपा नहीं है कि म्यांमार के रास्ते ड्रग्स भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचाया जा रहा है। वहां से यह ड्रग्स पूरे भारत में पहुंचता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी तस्करी बड़ी मात्रा में ड्रग्स पंजाब के



रास्ते और कश्मीर के रास्ते भारत भेज रहे हैं। आप कुछ आंकड़ों पर गौर करेंगे तो दंग रह जाएंगे। पिछले साल राजस्थान में यह जानकारी दी गई थी कि 2020 से 2023 के बीच जिन पांच राज्यों में सबसे ज्यादा ड्रग्स जब्त हुए उनमें करीब 2 लाख 93 हजार किलो ड्रग्स तमिलनाडु में जब्त किया गया। उसके बाद राजस्थान, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, ओडिशा और मध्यप्रदेश का नंबर था। आंकड़े बताते हैं कि 2004 से 2014 के बीच 5900 करोड़ रुपये मूल्य के ड्रग्स जब्त हुए जो अगले दस साल (2014-2024) में बढ़ कर 22 हजार करोड़ हो गया। ये तो वो आंकड़े हैं जो ड्रग्स जब्त हुए। सवाल यह है कि ड्रग्स नेटवर्क का किनारा ड्रग्स पकड़ा गया और किनवा युवाओं के शरीर में फैला गया? अभी तो यह पता नहीं है कि भारत में ड्रग्स का खतरनाक कारोबार आखिर कितनी राशि का है? बीच-बीच में कुछ बड़ी खेप पकड़ी जाती है लेकिन यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है कि

देश में हालात क्या हैं? पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली के महिलापुर में दिल्ली पुलिस ने एक गोदाम से 562 किलोग्राम कोकोन और थाईलैंड से आया 40 किलोग्राम मारिजुआना (गांजा) बरामद किया था। पुलिस ने ड्रग तस्करो के अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। उसी दौरान एक नेता का नाम भी सामने आया था। यह कहना जरूरतवाजी होगी कि राजनीति के लोग भी नशे के कारोबार में शामिल हैं लेकिन ऐसे मामलों में जब किसी नेता का नाम आता है तो यह शंका तो होती है कि नशे के कारोबारियों को राजनीति की तकत मिलती होगी अन्यथा हजारों करोड़ रुपये के ड्रग्स दिल्ली जैसी जगह में कैसे पहुंच जाते? कहीं न कहीं पुलिस से भी चुक चुकी होगी या कुछ लोग मिले होंगे। कारण जो भी हो लेकिन मौजूदा वक्त की सच्चाई यह है कि भारत नशे के कारोबारियों का शिकार होता जा रहा है। कुछ चलन ऐसा हो गया है।

मन्दिरों में पैसे लेकर एवं वीआईपी दर्शन बन्द हो

ललित गर्ग
थकुर बांके बिहारी मंदिर में पैसे लेकर दर्शन कराने वाले बाउंसर्स की गिरफ्तारी के बाद श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में सुगम दर्शन के नाम पर एक साथ इक्कीस लोगों की गिरफ्तारी जहां मंदिर प्रशासन की व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न है, वहीं ईश्वर के दरबार में पांव फैला रहा भ्रष्टाचार गहन चिन्ताजनक एवं शर्मनाक है। कुछ ही दिनों पहले ओकरेश्वर स्थित ममलेश्वर मंदिर में भक्तों से वीआईपी दर्शन के नाम पर अवैध वसुली करने पर प्रशासन ने एक लेम्पार्ड जवान और दो पीडियों पर कार्रवाई की है। देश-विदेश के भक्त अगाध ब्रह्मा से अपने आराध्य का दर्शन करने आते हैं, लेकिन देश के प्रमुख मन्दिरों में सीधे दर्शन कराने के नाम पर पैसों की लुट मची है या वीआईपी संस्कृति के नाम पर त्रासद एवं भेदभावपूर्ण स्थितियाँ पसरि है। सवाल यह पुछ जा रहा है कि हिंदुओं के धार्मिक स्थलों और आयोजनों में क्यों भक्तों के बीच भेदभाव होता है? मन्दिरों में गरीब एवं अमीर के बीच भेदभाव की स्थितियाँ खुला भ्रष्टाचार ही है। पैसे लेकर एवं वीआईपी दर्शन की अवधारणा भक्ति एवं आस्था के खिलनाक है। यह एक असमानता का उदाहरण है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी आपात करती है। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में तो त्रिसंतीय सुरक्षा व्यवस्था भी है। मंदिर का चप्पा-चप्पा सीसीटीवी कैमरे की पहुंच में है। यह मन्दिर सुरक्षा कारणों से अतिमंडेनशील स्थल होने के बावजूद ऐसा कृत्य खेदजनक ही नहीं, अपातिजनक भी है। मंदिर प्रबंधन को चाहिए कि दर्शन की प्रचलित व्यवस्था को और सुगम, भ्रष्टाचार व दोषरहित बनाए ताकि व्यवस्था में कोई संघर्ष न लगे और जन-आस्था आहत न हो। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में तो सुगम दर्शन का शुल्क भी जमा कराया जाता है पर एगों की जमात ने शीघ्र दर्शन के नाम पर कमाई का नया



रास्ता तलाश लिया। मंदिर प्रबंधन को चाहिए कि वह सुगम दर्शन व्यवस्था के नाम पर हो रही धोंधली को गंभीरता से ले। फर्जी पंख, गाइड बनकर लोगों को झांसे में लेने वाले लोग अचानक एक दिन में डेरा नहीं जमाए होंगे। यह सब काफी समय से चल रहा होगा। इस प्रकार की ठगी करने की संभावना कैसे बन जाती है, इसकी जांच होनी चाहिए। बात केवल थकुर बांके बिहारी मंदिर या श्रीकाशी विश्वनाथ धाम की ही नहीं है, बल्कि देश के प्रमुख मन्दिरों में बढ़ती जन-आस्था की भीड़ एवं लम्बी-लम्बी लाइनों के बीच पैसे लेकर या वीआईपी दर्शन कराने की त्रासद एवं विसंगतिपूर्ण स्थितियों की है, जिसने न केवल देश के आम आदमी के मन को आहत किया है, बल्कि भारत के समानता के सिद्धान्त की भी धाँजियाँ उछा दी है। कुछ विशेष लोगों को मिलने वाले वीआईपी सम्मान एवं सुविधा पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। बांके बिहारी मंदिर में एक बार फिर वीआईपी कल्चर का खेल सामने आया है। मंदिर की भीड़ से हटकर वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर एक निजी सुरक्षा एजेंसी ने बाउंसर उपलब्ध कराकर पैसे कमाने का गोरखधंधा

शुरू कर दिया था। एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रचार कर यह दावा किया कि वे ब्रह्माजनों को भीड़ से बचाकर विशेष वीआईपी दर्शन कराने में मदद कर सकते हैं। यह तो घोषित गैरकानूनी व्यवस्था है, लेकिन अन्य प्रमुख मन्दिरों में भी मन्दिर से जुड़े लोग या अन्य ठग पैसे लेकर दर्शन कराते हैं। सबसे ज्यादा दुखद एवं विडम्बनपूर्ण है वीआईपी दर्शन का प्रचलन। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पहले ही कार्यकाल के दौरान वीआईपी कल्चर को खत्म करते हुए लालबत्ती एवं ऐसी अनेक वीआईपी सुविधाओं को समाप्त कर दिया था तो मन्दिरों एवं धार्मिक आयोजनों की वीआईपी संस्कृति को क्यों नहीं समाप्त किया? क्यों मन्दिरों में वीआईपी दर्शन के लिये सरकार ने अलग से व्यवस्थाएँ की। दरअसल, वीआईपी संस्कृति का दायरा बहुत व्यापक है। यह धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र से लेकर आस्था तक, कई मौकों पर कुछ खास लोगों को विशेष सुविधाएँ दी जाती हैं। लोकतंत्र का मूल सिद्धान्त कहता है कि सभी नागरिक समान हैं, फिर भी व्यवहार में कुछ

लोग 'विशेष' बन जाते हैं, चाहे वे सड़क पर हों, सरकारी दफ्तरों में, अस्पतालों में या मंदिरों में। इसी तरह, बड़े नेताओं और अधिकारियों के लिये मन्दिरों में सीधे दर्शन कराने की व्यवस्थाएँ हैं, जिससे लम्बी कतारें और लम्बे समय का इंतजार करती है। ऐसी व्यवस्था से मन्दिरों एवं धार्मिक आयोजनों में हदसे भी होते हुए देखे गये हैं। इन वीआईपी के लिए अक्सर यातायात रोक दिया जाता है, जिससे आम जनता घंटों जाम में फंसी रहती है। अस्पतालों में वीआईपी वार्ड हैं, जबकि आम मरीजों को बिस्तर भी नहीं मिल पाता। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर वीआईपी यात्रियों को विशेष सुविधाएँ मिलती हैं, जबकि आम लोग लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। वीआईपी संस्कृति एक नासूर बन गई है। यही कारण है कि हर सरकारी वीआईपी संस्कृति को खत्म करने का वादा करती है, लेकिन हकीकत में इसे बनाए रखने के नए-नए तरीके खोजे जाते हैं। वीआईपी कल्चर एवं पैसे लेकर दर्शन कराने की धोंधली ने एक बार फिर से नये सिरे से बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहा है कि जब गुरुद्वारे में वीआईपी दर्शन नहीं, मस्जिद में वीआईपी नमाज नहीं, चर्च में वीआईपी प्रार्थना नहीं होती है तो सिर्फ हिन्दू मंदिरों में कुछ प्रमुख लोगों के लिए वीआईपी या पैसे लेकर दर्शन क्यों है? क्या इस पद्धति को खत्म नहीं किया जाना चाहिए, जो हिंदुओं में दूरिया पैदा करता है? प्रसिद्ध मन्दिरों में वीआईपी पास एवं दर्शन की व्यवस्था समाप्त क्यों नहीं होती? यह व्यवस्था समाप्त होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति जवाहीर धनखड़ ने ही धार्मिक स्थलों पर होने वाली वीआईपी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किये हैं। निश्चित ही जब किसी को वरीयता दी जाती है और प्राथमिकता दी जाती है तो उसे वीवीआईपी या वीआईपी कहते हैं। यह समानता की अवधारणा को कमतर आंकना है।

वंशवाद के झगड़े बदल सकते हैं राजनीति?

प्रभु चावला
जहां भाई-बहन, भतीजे और बेटे जाति, समुदाय और क्षेत्रीय गर्व के नाम पर लड़ते रहते हैं। बीआरएस के तेलुगु क्षेत्र से एनसीपी के महाराष्ट्र तक, सपा के यादव वर्चस्व से राजद के ओबीसी वर्चस्व तक, बसपा के दलित सपनों से तुणमूल के बंगाली जोश तक, द्रमुक की द्रविड़ जड़ों से पीएमके की रूढ़िवादी पहचान तक एक ही प्रवृत्ति दिखती है। ये तमाम पार्टियाँ सामाजिक और क्षेत्रीय पहचान पर फलती-फूलती हैं, लेकिन इनके पारिवारिक विवाद इन सच्चाइयों की असंख्य उखाड़ देते हैं। क्या वे राजनीतिक वंशज झगड़ों के बाद भी राजनीतिक अस्तित्व बनाए रख सकेंगे? क्या समृद्धि और शिक्षा इन वंशवादी पार्टियों को खत्म कर देगी? और इनके राजनीतिक भाग्य का हमारी राजनीतिक पार्टियों के भविष्य से क्या लेना-देना है? स्वतंत्र तेलंगाना राज्य आंदोलन की दौरान जन्मी बीआरएस ने तेलुगु स्वाभिमान को अपना आधार बनाया, लेकिन कविता के विद्रोह और पार्टी पर केंटीआर की मजबूत पकड़ ने बता दिया है कि पार्टी अपनी पहचान खो सकती है। केंसीआर इस मुद्दे पर खामोश है, लेकिन उसकी संतानों का आसपी झगड़ा उन मतदाताओं को पार्टी से दूर कर सकता है, जो स्वतंत्र तेलंगाना राज्य के लिए एकजुट हुए थे। अगर बीआरएस बिखरती है तो भाजपा और काँग्रेस इसका लाभ उठाएंगी। बिहार में राजद ओबीसी तथा मुस्लिम वोट बैंक और लालू प्रसाद की खण्ड विरोधी विरस पर टिका है। उनके बेटे तेजप्रताप और तेजस्वी के बीच विवाद है। तेजप्रताप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 'जयचंदी' का जिक्र है और पुराने रोमांस का भी। इस पर तेजप्रताप की अलग हो चुकी पत्नी ऐश्वर्या को शिकायती प्रतिक्रिया मतदाताओं को पार्टी से दूर कर सकती है। अगर राजद अलग-थलग पड़ जाता है, तो राज्य के युवा फिर भाजपा या नीतीश कुमार के पाले में जा सकते हैं। लेकिन अगर तेजस्वी के दिशानिर्देश में राजद मजबूत होकर उभरता है, तो इससे भाजपा के वर्चस्व को चुनौती मिलेगी और महाराष्ट्रबंधन में काँग्रेस को राजद के पीछे-पीछे चलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में यादव और ओबीसी पहचान पर आधारित सपा अब भी 2016 के पारिवारिक विवाद से उबर नहीं पाई है। हालाँकि अखिलेश अब सपा के वोट बैंक के साथ मजबूती से खड़े हैं, पर प्रदेश के शहरी युवा जातिवाद से कम प्रभावित हैं। यदि सपा और विखंडित होती है तो हिंदुत्व और विकास मॉडल के जरिये भाजपा राज्य में और मजबूत होगी तथा काँग्रेस को और भी हारिये पर धकेल देगी। दूसरी तरफ यादव-मुस्लिम जनाधार को मजबूती से धामने हुए सपा अगर एकजुट होती है तो भाजपा को तगड़ी चुनौती मिल



सकती है। एनसीपी ने मराठा गौरव और मजबूत ग्रामीण नेटवर्क से महाराष्ट्र में अपना मजबूत जनाधार बनाया था। लेकिन 2023 में अजित पवार के भाजपा के साथ जाने के सदमे से पार्टी अब भी उबर नहीं पाई है। अगर यथास्थिति बनी रहती है तो भाजपा और उसकी सहयोगी शिवसेना का वर्चस्व बना रहेगा, जबकि काँग्रेस को शहरी इलाकों में थोड़ा-बहुत समर्थन मिलेगा। लेकिन अगर एनसीपी एकजुट होती है, तो वह किंगमेकर बन सकती है। दलितों के सरक्षितकरण का लक्ष्य लेकर बसपा आगे बढ़ी और मायावती इसका केंद्रबिंदु बनीं। पार्टी में अपने भाई आनंद कुमार और भतीजे आकाश आनंद को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का मायावती का फैसला भाई-भतीजेवाद का ही अनुपम उदाहरण था। जाटव और दलित बसपा का वोट बैंक रहे हैं, पर शक्ति दलितों के भाजपा के विकास कार्य से अकारणित होने के कारण बसपा का जनाधार सिकुड़ रहा है। अगर बसपा वंशवाद के बोझ तले दब जाती है तो भाजपा इसका लाभ उठाएगी और उत्तर प्रदेश में खुद को और मजबूत करेगी, जबकि काँग्रेस को शहरी दलितों के ही कुछ वोट मिल पाएंगे, दूसरी ओर, यदि मायावती अपनी सक्तिता छोड़ती हैं और आकाश आनंद के नेतृत्व में बसपा खुद को मजबूत बना लेती है तो उत्तर प्रदेश की ज्वति राजनीति में बसपा राष्ट्रीय पार्टियों को चुनौती देने की स्थिति में होगी। पश्चिम बंगाल में तुणमूल काँग्रेस ममता बनर्जी के दिशानिर्देश पर चलती है और अभिषेक बनर्जी उनके उत्तराधिकारी हैं। सांसद और महसुसचिव के रूप में तुणमूल में अभिषेक के उथान ने पार्टी के अनेक विरिष्ठों को असहज किया है। अभी तो पार्टी में सब कुछ ठीक है लेकिन ममता के बाद पार्टी अगर टूटती है तो राज्य के मतदाता भाजपा के पाले में जा सकते हैं। दूसरी तरफ, अभिषेक के नेतृत्व में एकजुट तुणमूल राष्ट्रीय पार्टियों को उसके साथ खड़े होने के लिए विवश कर सकती है। तमिलनाडु में करुणानिधि के पुत्र एम.के. स्टालिन उदरनिधि को अपना उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। द्रमुक का नेतृत्व मजबूत है, लेकिन तमिलनाडु में आईटी सेक्टर के जिन युवाओं के जरिये समृद्धि आई है।

भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों में पिता को देवतुल्य माना गया है। हमारे ग्रन्थों में माता-पिता और गुरु तीनों को ही देवता माना गया है। इनकी सेवा और भक्ति में कसर रह जाए तो फिर ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं। भारतीय संस्कृति में पिता का स्थान आकाश से भी ऊँचा माना गया है, पिता की धर्म है, पिता ही संबल है, पिता ही ताकत है। पिता हर संतान के लिए एक प्रेरणा है, एक प्रकाश है और संवेदनाओं के पुंज हैं। इसके महत्व को दर्शाने और पिता व पिता तुल्य व्यक्तियों के योगदान को सम्मान देने के लिए हर साल जून महीने के तीसरे रविवार को अंतर्राष्ट्रीय पिता दिवस यादनी फादर्स डे मनाया जाता है। इस साल 15 जून 2025 को भारत समेत विश्वभर में यह दिवस मनाया जायेगा। फादर्स डे 2025 का आधिकारिक थीम 'पिता: लचीलेपन का पोषण और भविष्य को आकार देना' है। यह थीम हमारे जीवन में पिताओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है, जो बच्चों में सकारात्मक भावनाओं और सामाजिक विकास को बढ़ावा देते

पिता-पुत्र का रिश्ता बेजोड़ एवं विलक्षण है

है। दुनिया के अलग-अलग देशों में अलग-अलग दिन और विविध परंपराओं के कारण उत्साह एवं उमंग से यह दिवस मनाया जाता है। यह एक ऐसा दिन है जिसे अपने पिता के सम्मान के लिए मनाया जाता है, साथ ही पितृत्व, पौतक बंधन और समाज में पिताओं के प्रभाव को भी याद किया जाता है। हिन्दू परंपरा के मुताबिक पितृ दिवस भाद्रपद महीने की सर्वोपेतु अमावस्या के दिन होता है। पिता एक ऐसा शब्द जिसके बिना किसी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक ऐसा पवित्र रिश्ता जिसकी तुलना किसी और रिस्ते से नहीं हो सकती। पिता ईश्वर का सबसे अच्छा उपहार है। जीवन में कोई भी पिता की जगह नहीं ले सकता। पिता अपनी संतान के सच्चे शुभचिंतक एवं हितैषी होते हैं। सोनेरा डोड जब नन्ही-सी थी, तभी उनकी माँ का देहांत हो गया। पिता विलियम स्मार्ट ने सोनेरी

के जीवन में माँ की कमी नहीं महसूस होने दी और उसे माँ का भी प्यार दिया। एक दिन चूँ ही सोनेरा के दिल में ख्याल आया कि आखिर एक दिन पिता के नाम क्यों नहीं हो सकता? इस तरह 19 जून 1910 को पहली बार फादर्स डे मनाया गया। 1924 में अमेरिकी राष्ट्रपति कैल्विन कोली ने फादर्स डे पर अपनी सस्मृति दी। फिर 1966 में राष्ट्रपति लिंडन जानसन ने जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाने की आधिकारिक घोषणा की। पिता ही बच्चों की सुरक्षा, विकास व समृद्धि के बारे में सोचते हैं। बावजूद बच्चों द्वारा पिता की लगातार उपेक्षा, दुर्व्यवहार एवं प्रताड़ना की स्थितियों बढ़ती जा रही है, जिन पर निर्वर्ण के लिये इस दिवस की विशेष उपयोगिता एवं प्रासंगिकता है। मानवीय रिश्तों में दुनिया में सबसे बड़ा स्थान माँ को दिया जाता है, लेकिन एक बच्चे को बड़ा और सम्य

बनाने में उसके पिता का योगदान कम करके नहीं आँका जा सकता। पिता नीम के पेड़ जैसा होता है उसके पत्ते भले ही कड़वे होते हैं पर जो छाया डंडी देता है। पिता और बच्चों का रिश्ता इस दुनिया में सबसे अलग होता है। एक तरफ पिता बच्चों को खटते हैं, तो दूसरी तरह बच्चों से बेहद प्रेम भी करते हैं। पिता अपने बेटे की चोट पर व्यथित तो होता है लेकिन उसे बेटे के सामने मजबूत बने रहना है। ताकि बेटा उसे देख कर जीवन की समस्याओं से लड़ने का पाठ सीखे, सख्त एवं निडर बनकर जिंदगी की तकलीफों का सामना करने में सक्षम हो। भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों में पिता को देवतुल्य माना गया है। हमारे ग्रन्थों में माता-पिता और गुरु तीनों को ही देवता माना गया है। इनकी सेवा और भक्ति में कसर रह जाए तो फिर ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं। और अगर हमने इनकी सेवा पूरे मन से की तो भगवान स्वयं कच्चे धगे से बंधे भक्त के पीछे-पीछे चल पड़ते हैं। इस दिवस को मनाने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं।



ग्रीष्मकालीन ताइक्वांडो, वूशु कराते, पेंचिक सिलाट समर कैंप में सम्मिलित खिलाड़ियों की हुई प्रतियोगिता

मंदसौर, 17 जून गुरु एक्सप्रेस। मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन मंदसौर के संचालक अध्यक्ष श्री गगन कुरील ने बताया की मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन मंदसौर एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तत्वधान में चल रहा 29 वा ग्रीष्मकालीन ताइक्वांडो, वूशु कराते, पेंचिक सिलाट मार्शल आर्ट समर कैंप 15 मार्च से 15 जून 2025 तक तीन महीने चले शिविर में भाग लिए खिलाड़ियों की 14 जून को महारानी लक्ष्मी बाई विद्यालय में प्रतियोगिता आयोजित की गई स जिसमें मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन के द्वारा

प्रतियोगिता का शुभारंभ के मुख्य अतिथि वरिष्ठपत्रकार एवं जिला स्पोर्ट्स ताइक्वांडो एसोसिएशन मंदसौर के अध्यक्ष सुरेश जी भाटी, कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय ग्राहक संचालक एवं जिला पेंचिक सिलाट

एसोसिएशन मंदसौर के अध्यक्ष विजय जी कोठारी, विशेष अतिथि शासकीय कन्या महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय के प्रिंसिपल कै.सी जी सोलंकी, पार्षद आशीष जी गौड़, पूर्व डीएसपी पुलिस विभाग अब्दुल रशीद खान, सिटी कोतवाली के दीवान मनोहर जी मसानिया, पुलिस विभाग से आनंद जी राठौड़ जी, आशीष जी मंत्री, जितेंद्र जी राव, सुरेश जी बोराना सर मंचासीन थे अतिथियों द्वारा प्रतियोगिता संपन्न करवाने वाले निर्णायक हेड जज सैयद आफताब आलम सेन्टर रिकेरी धवल कुमार कोनर जय शी हो, सोनू मेघवाल, कृष्णा गडिया, तुलसी बैरागी, संदीप आर्य, आसमा बी दिव्यांश सोलंकी, दीपेश गहलोत, तुषार गुर्जर, आरती आर्य सभी निर्णायक को समुति चिन्ह प्रदान किया गया अतिथियों का स्वागत सैयद आफताब आलम, सुनील हीवे, अशोक माली, कमलेश जी डोसी, शाहिद जी हुसैन, यशवंत सिंह राठौर, दुर्गा बेलाणी द्वारा किया गया कार्यक्रम का संचालन मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संचालक गगन कुरील ने किया एवं आभार टेविनकल डायरेक्टर सैयद आफताब आलम ने माना।

कलेक्टर ने जनसुनवाई में 152 आवेदकों की सुनी समस्याएं

नीमच, 17 जून गुरु एक्सप्रेस। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में जनसुनवाई करते हुए 152 आवेदकों की सुनी समस्याएं और उनका निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस मौके पर जिला पंचायत श्रीमती श्री अमन वैष्णव, एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड, संयुक्त कलेक्टर डॉ.ममता खेडे, श्री राजेश शाह, एसडीएम श्री संजीव साहू, सभी डिप्टी कलेक्टर एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में कलेक्टर श्री चंद्रा ने धनेरिया कला निवासी कनीराम एवं मुकेश के आवेदन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास करने वालों, डराने, धमकाने वालों और जबरन कब्जा करने के प्रयास करने वालों के विरुद्ध पटवारी को तत्काल मौके पर भेजकर कार्यवाही करने के निर्देश एसडीएम नीमच को दिए। ग्राम बरकटी के हीरालाल मीणा के आवेदन पर कलेक्टर ने हीरालाल की जमीन बिक्री की कीमत (राशि) प्रदान नहीं करने एवं राशि मांगने पर अभद्र व्यवहार करने वालों के विरुद्ध जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश तहसीलदार जीरन को दिए। जनसुनवाई में लासुडीआंजी के नरेंद्र, भरमडिया के गणपूाल, बाजुराम, चैनराम, बघाना के



वीरेंद्र कुमार, एकता कॉलोनी नीमच की दुलाशीबाई, तारपुर की शकीला बागु, बरखेडाहाडा के दशरथ, कराडिया लेवडा के विवेन्द्र सिंह, कवरलाल, सिटी के नाजबीन, जीरन के ओमप्रकाश पाटीदार, के शरपुरा के नंदलाल, खुशालपुरा के कारुलाल गुर्जर, हुडको कॉलोनी नीमच के नवीन जैन, जमुनिया खुर्द के भेरुलाल खारोल, धनेरियाकलां के चिरंजीवी नागवा, नलखेडा के जगदीशचंद्र, गरीब मोहला नीमच की मुनीबाई, मानपुरा के राधेधाम धाकड आदि ने अपनी समस्याओं से संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए। इसी तरह बराडा की रूमकणबाई, जीरन के नरेंद्र कुमार, कंजार्ज की नोजीबाई, बांगरे के मुकेश बंजारा, दलपतपुरा के डाडमचंद,

मालखेडा की मोहनीबाई, अघोरिया के कचरुलाल, बर्डियाजगीर के देवकिशन, जमुनिया कलां की सुनीता मालवीय, लेवडा के विवेन्द्र सिंह, कवरलाल, प्रहलाद, मूलचंद, हरवार के मनोरंजलाल, रेवली देवली के प्रमोदास, धामनिया के अशोक कुमार, सरवानिया

महाराज के युसुफ एजाज मोहम्मद, कनावटी के मन्नालाल लोहार आदि ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन जनसुनवाई में प्रस्तुत किए। जिस पर कलेक्टर ने आवेदनों का निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।

गायत्री परिवार द्वारा हर्बल गार्डन में किया श्रमदान

मंदसौर, 17 जून गुरु एक्सप्रेस। गायत्री परिवार द्वारा नगर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। गार्डन की साफ सफाई, पेड़ों की छाई का कार्य भी समय-समय पर कॉलोनीयों में जाकर किया जा रहा है। मिशन 2026 के अंतर्गत जो कार्यविराम पड़े हैं उन सभी पाक में सफाई व पेड़ लगाने का अभियान चलाया जायेगा। सभी पार्क में गायत्री परिवार के साथ मिलकर धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएं जन सहयोग कर कार्य कर सकती हैं। इस संबंध में गायत्री परिवार कार्यालय में लिखित में दे सकते हैं। जिन कॉलोनीयों के पार्क की सफाई करना है वे भी लिखित में दे जिससे वहां सफाई अभियान चलाकर पार्क की सुंदरता को बढ़ाया जा सके शासन प्रशासन भी इस कार्य में सहयोग प्रदान करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद का निर्णय...

459 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना, संचालन एवं भवन निर्माण के लिए 143 करोड़ 46 लाख रुपये की स्वीकृति

नीमच, 17 जून गुरु एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 का अनुमोदन किया गया है। अनुमोदन अनुसार आरक्षित वर्गों की प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर उनके हितों को संरक्षित किया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिये 20% एवं अनुसूचित जाति के लिये 16% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोकसेवकों को भी मेरिट के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करने का अवसर दिया गया है। वर्तमान वर्ष में ही आगामी वर्ष की रिक्तियों के लिए पदोन्नति समिति की बैठक कर चयन सूची बनाये जाने का प्रावधान किया गया है, अर्थात अग्रिम डी पी.सी. के प्रावधान किये गये हैं। पदोन्नति के सूत्र में वरिष्ठा का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। वरिष्ठ लोक सेवकों में से मेरिट के अनुसार न्यूनतम अंक लाने वाले लोक सेवक पदोन्नति के लिए पात्र होंगे, प्रथम श्रेणी के लोक सेवकों के लिए merit cum seniority का प्रावधान किया गया है। पदोन्नति के सूत्र में कार्यदक्षता को प्रोत्साहित किया जाना लक्षित है, पदोन्नति के लिए अपात्रता का स्पष्ट निर्धारण किया गया है। किफ परिस्थितियों में कोई लोक सेवक अपात्र होगा एवं रण्ड का क्या प्रभाव होगा यह स्पष्टरूप से लेख किया गया है। किसी भी विभागीय पदोन्नति समिति बैठक के सन्दर्भ में निर्णय के



पुनर्विलोकन के लिए रिज्यू.डी.पी.सी. की बैठक आयोजित किये जाने के लिये स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं। नवीन पदोन्नति नियमों में परिभ्रमण की व्यवस्था समाप्त की गई है। इससे पदोन्नति के लिए अधिक पद हो सकेंगे। पदोन्नति समिति को शासकीय सेवक की उपयुक्तता निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है। चतुर्थ श्रेणी के लिये अंक व्यवस्था नहीं होगी, केवल पदोन्नति के लिए उपयुक्त होने पर ही पदोन्नति प्राप्त हो सकेगी। अर्हकारी सेवा के लिए किसी वर्ष में की गई आंशिक सेवा को भी पूर्ण वर्ष की सेवा माना जायेगा, यदि वर्ष के एक भाग की सेवा भी की गई है तो उसे पूर्ण वर्ष की सेवा माना जाएगा। यदि किसी वर्ष में 6 माह का ही गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध है तो उसे पूर्ण वर्ष के लिये मान्य किया जा सकेगा। यदि गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी की पदोन्नति रकृती है तो उसे पदोन्नति प्राप्त होने पर पूरी वरिष्ठा दी जायेगी। अप्रत्याशित रिक्तियों को चयन सूची/प्रतीक्षा सूची से भरे जाने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए शासकीय सेवक (जो आगामी वर्ष अर्थात् पदोन्नति वर्ष में उपलब्ध नहीं होंगे) के पद के

विरुद्ध पदोन्नति का प्रावधान किया गया है। गोपनीय प्रतिवेदनों में से यदि कोई गोपनीय प्रतिवेदन एन.आर.सी (नो रिपोर्ट सर्टिफिकेट), सक्षम स्तर से स्वीकृत अवकाश, पदग्रहण काल अथवा प्रशिक्षण के कारण है अथवा गोपनीय प्रतिवेदन में निर्धारित समय पर स्वमूल्यांकन के साक्ष्य है तो ऐसी स्थिति में गोपनीय प्रतिवेदन की अनुपलब्धता के आधार पर पदोन्नति नहीं रोकी जायेगी। विभागीय पदोन्नति समिति के बैठक से पूर्व केवल कारण बताओ सूचना पत्र के आधार पर बंद लिफाफा की कार्यवाही नहीं की जायेगी, जिससे अधिक लोक सेवकों को पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर पदोन्नति के पद जिस दिन उपलब्ध हो उसी दिन उपयुक्त योग्य एवं आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व के ध्यान में रखकर भरे जा सकें। इस तरह से लगभग 2 लाख नए पद निर्मित होंगे। इससे प्रशासन में सुधार एवं कार्यक्षमता बढ़ेगी।

459 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना, संचालन तथा भवन निर्माण के लिए 143 करोड़ 46 लाख रुपये की स्वीकृति-मंत्रि-परिषद द्वारा 'सक्षम आंगनवाड़ी' एवं पोषण 2.0 योजना अंतर्गत विशेष जनजाति क्षेत्रों में

PM-DANMAN कार्यक्रम के लिए 459 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना, संचालन तथा भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी।स्वीकृति अनुसार 459 आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 459 पद (मानसेवी), आंगनवाड़ी सहायिका के 459 पद (मानसेवी) तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षक के 26 पद (नियमित शासकीय सेवक पद वेतनमान 25,300-80,500) के सृजन की स्वीकृति दी गयी है।वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक योजना पर राशि राशि रिपोर्ट सर्टिफिकेट), सक्षम स्तर से स्वीकृत अवकाश, पदग्रहण काल अथवा प्रशिक्षण के कारण है अथवा गोपनीय प्रतिवेदन में निर्धारित समय पर स्वमूल्यांकन के साक्ष्य है तो ऐसी स्थिति में गोपनीय प्रतिवेदन की अनुपलब्धता के आधार पर पदोन्नति नहीं रोकी जायेगी। विभागीय पदोन्नति समिति के बैठक से पूर्व केवल कारण बताओ सूचना पत्र के आधार पर बंद लिफाफा की कार्यवाही नहीं की जायेगी, जिससे अधिक लोक सेवकों को पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर पदोन्नति के पद जिस दिन उपलब्ध हो उसी दिन उपयुक्त योग्य एवं आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व के ध्यान में रखकर भरे जा सकें। इस तरह से लगभग 2 लाख नए पद निर्मित होंगे। इससे प्रशासन में सुधार एवं कार्यक्षमता बढ़ेगी।

परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए यथा केंद्रीय पारेषण इकाई से स्वीकृत पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण के लिए आवश्यक निर्माण और उन्नयन कार्य के लिए 1 हजार 154 करोड़ रुपये, सिंहस्थ-2028 के लिए आवश्यक कार्य के लिए 185 करोड़ रुपये, प्रदेश में नवीन अति उच्चदाब उपकेन्द्रों का निर्माण के लिए 1 हजार 15 करोड़ रुपये, मुरैना संभागीय मुख्यालय और खालियर शहर के उत्तरी भाग को अनवरत विद्युत् आपूर्ति के लिए नवीन अति उच्चदाब लाइनों के निर्माण के लिए 54 करोड़ रुपये, प्रदेश में विद्यमान अति उच्चदाब ट्रांसफार्मरों की क्षमता संवर्धन/वृद्धि के लिए 1280 करोड़ रुपये, आरडीएसएस योजना के अंतर्गत वितरण कंपनियों के लिए 184 नए नवीन 33 केव्ही बे निर्माण के लिए 81 करोड़ रुपये, डीपी / एफपी लाइन (डबल पोल/फोर पोल) लाइन को डीसीडीएस / डीसीएसएस (डबल सर्किट डबल स्ट्रन्ग/डबल सर्किट सिंगल स्ट्रन्ग) टॉवर लाइन में रूपांतरण के लिए 662 करोड़, अति उच्चदाब टैप लाइनों के स्थापन पर लाइनों का लूप-इन लूप-आउट (एलएलएलओ)-किया जाना एवं एकल स्रोत से प्रदायित उपकेन्द्रों के लिए नई लाइनों का निर्माण के लिए 451 करोड़ रुपये तथा अन्य कार्य जिसमें SCADA प्रणाली का प्रतिस्थापन, 132 केवी द्वितीय मुख्य बस तथा 132/33 केवी बस कमलर का निर्माण, 33 केवी कैपेसिटर बैंक की स्थापना एवं अन्य कार्य) के लिए 281 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

पुलिस वालों का व्यवहार बताने लगाएं क्यूआर कोड

शिकायतकर्ता को बताना होगा-कैसा किया पुलिस ने बर्ताव

भोपाल, 17 जून गुरु एक्सप्रेस। अब हर एफआईआर के बाद शिकायतकर्ताओं को थाने में पुलिसकर्मियों के व्यवहार के संबंध में फीडबैक भी देना होगा। बताना होगा कि थाने में उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया। पुलिसकर्मियों ने अच्छे से बात की या नहीं। समस्या को ठीक से सुना या नहीं। इसके लिए थानों में क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं। इसको स्कैन करने के बाद शिकायतकर्ता ऑनलाइन फीडबैक भर सकेगा। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। किसी खुले स्थान पर क्यूआर

कोड लगाया जाएगा। जिसे स्कैन कर लोग सेवाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकेंगे। फीड बैक के आधार पर कमियों को दूर करेंगे। क्यूआर कोड को गुगल या एनआरसी के माध्यम से फॉर्म को जनरेट किया जाएगा। इसकी कोड पुलिस कमिश्नर की ई-मेल आईडी से लिंक होगी।

यह जानकारी देनी होगी-
* नाम और मोबाइल नंबर
* अपराध नियंत्रण की स्थिति
* क्षेत्र में यातायात व्यवस्था
* सामाजिक गतिविधियों के दौरान पुलिस व्यवस्था
* आपदा के समय सहयोग
* पुलिसकर्मियों का व्यवहार

* पुलिसकर्मियों की कार्य दक्षता
* थाना भवन की साफ सफाई
* थाना भवन में उपलब्ध संसाधन
* आगंतुकों की बैठने की व्यवस्था

इनका कहना-देवास में इस व्यवस्था को पहले लागू किया गया था। अब मुख्यालय से पूरे प्रदेश में इसे लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यालय ने क्यूआर स्कैन कोड बनाया है। इसका फॉर्मेट सभी को दिया गया है।

पवन श्रीवास्तव
एडीजी, पुलिस मुख्यालय



एकेडमी में चयन हेतु 100 हॉकी खिलाड़ियों का ट्रायल किया

मंदसौर, 17 जून गुरु एक्सप्रेस। जिला खेल अधिकारी श्री विजेंद्र देवडा द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन के खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित मध्य प्रदेश हॉकी पुरुष हॉकी एकेडमी में खिलाड़ियों के चयन हेतु ट्रायल का आयोजन हॉकी एस्ट्रो टर्फ मंदसौर पर किया गया। मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के हेड कोच श्री समीर दाद, श्री लोकेन्द्र भार्गव और कंडीशनिंग कोच श्री आरिफ द्वारा मंदसौर, रतलाम, नीमच से खिलाड़ी उपस्थित हुए। 12 से 18 आयु वर्ग के 100 हॉकी खिलाड़ियों का ट्रायल किया गया। जिसमें रिकल टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट एवं मैच प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ीयों का आंकलन किया गया। और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को फाइनल ट्रायल के लिए भोपाल हॉकी एकेडमी में जाने हेतु चयनित किया गया।

जनसुनवाई में 107 मामलों में सुनवाई की

मंदसौर, 17 जून गुरु एक्सप्रेस। जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग व अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन द्वारा सुशासन भवन सभाकक्ष में 107 आवेदकों की समस्याएं सुनीं। अधिकारियों को जल्दी निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मंदसौर जिले के मोहम्मदपुरा निवासी आवेदक बालाराम माली ने मकान के पास विद्युत खम्बे को हटाने के संबंध में आवेदन दिया। जिस पर एमपीईबी विभाग मंदसौर को निर्देश दिए कि जांच कर कार्यवाही करें। मंदसौर जिले के मजसेरा निवासी देवीलाल ने संबल योजना का लाभ नहीं मिलने के संबंध में आवेदन दिया। जिस पर सीईओ जनपद मंदसौर को निर्देश दिए कि जांच कर कार्यवाही करें। मंदसौर निवासी आवेदक संगीता ने आर्थिक सहायता के संबंध में आवेदन दिया। जिस पर नगर पालिका सीएमओ मंदसौर को निर्देश दिए कि जांच कर कार्यवाही करें। मंदसौर जिले के केल्खेडी निवासी आवेदक उदा ने खेत पर आने-जाने का रास्ता खुलवाने के संबंध में आवेदन दिया। जिस पर तहसीलदार सितामऊ को निर्देश दिये कि जांच कर कार्यवाही करें। इसके साथ ही जनसुनवाई के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करने, कृषि भूमि पर कब्जा व फसल नुकसान, प्रधानमंत्री आवास, अतिक्रमण हटाने, स्वीकृत राशी जमा नहीं होने, इत्यादि तरह-तरह के आवेदन आयें।

मंदसौर, 17 जून गुरु एक्सप्रेस। जिला आयुष अधिकारी डॉ कमलेश धनोतिया द्वारा बताया गया कि 21 जून 2025 को ग्यारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के विषय पर संपूर्ण विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना से एक साथ मुख्य समारोह में मनाया जाएगा। योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है। योग चित्त वृत्ति निरोधः चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है। योग स्वस्थ जीवन की कला एवं विज्ञान है। योग अभ्यास शरीर एवं मन, विचार एवं कर्म, आत्म संयम एवं पूर्णता की एकात्मकता तथा मानव एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य प्रदान करता है।

एनसीसी का दस दिवसीय शिविर सांस्कृतिक उत्सव के साथ संपन्न

कैंडेट्स की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध, विविध गतिविधियों में देखी बहुआयामी प्रतिभा

मंदसौर, 17 जून गुरु एक्सप्रेस। 5 मध्यप्रदेश बटालियन एनसीसी द्वारा आयोजित दस दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का समापन रंगारंग सांस्कृतिक संध्या के साथ हुआ। 8 जून से प्रारंभ हुए इस शिविर में कैंडेट्स ने न केवल सैन्य अनुशासन और कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि कला, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों में भी अपनी भागीदारी से सभी का मन मोह लिया। समापन समारोह की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जिसके पश्चात कैंडेट्स द्वारा मंच पर प्रस्तुत लोकनृत्य, गीत और नाट्य दृश्यों ने उपस्थितजनों को लोक-संस्कृति की समृद्ध झलक प्रदान की। इस अवसर पर बटालियन के कमान अधिकारी द्वारा उत्कृष्ट कैंडेट्स को सम्मानित किया गया। उन्होंने कैंडेट्स के अनुशासन, परिश्रम और लगन की सराहना करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर और राष्ट्रभक्त नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। शिविर के दौरान कैंडेट्स को



शारीरिक प्रशिक्षण, फायरिंग, प्राथमिक चिकित्सा, साइबर सुरक्षा, सैन्य योजना, ट्रैफिक नियंत्रण और आपदा सैन्य अनुशासन और कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि कला, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों में भी अपनी भागीदारी से सभी का मन मोह लिया। समापन समारोह की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जिसके पश्चात कैंडेट्स द्वारा मंच पर प्रस्तुत लोकनृत्य, गीत और नाट्य दृश्यों ने उपस्थितजनों को लोक-संस्कृति की समृद्ध झलक प्रदान की। इस अवसर पर बटालियन के कमान अधिकारी द्वारा उत्कृष्ट कैंडेट्स को सम्मानित किया गया। उन्होंने कैंडेट्स के अनुशासन, परिश्रम और लगन की सराहना करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर और राष्ट्रभक्त नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। शिविर के दौरान कैंडेट्स को

योग प्रशिक्षक श्री बंशीलाल टांक और सुश्री आस्था भावसार ने योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉ. छवि द्वारा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर जानकारी दी गई, जिससे कैंडेट्स को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की प्रेरणा मिली। डॉ. हिमांशु यजुर्वेदी ने थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया पर उपयोगी जानकारी प्रदान की। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं यातायात नियमों की जागरूकी दी गई, जिससे कैंडेट्स में एक जिम्मेदार नागरिक बनने की चेतना विकसित हुई।

चोरों के आगे बेबस सुवासरा पुलिस, अब तो पुलिस को मुंह चिढ़ाने लगी चोरी की वारदातें...

विधायक के घर के सामने और थाने से 100 मीटर दूर गुरुद्वारा साहिब में हजारों की चोरी

सुवासरा, 17 जून गुरु एक्सप्रेस। नगर सहित क्षेत्र में आए दिन होने वाली चोरी की वारदातों से लोग परेशान हैं। इधर पुलिस के सुस्त रवये के चलते इन वारदातों में अंकुश नहीं लग पा रहा है। जिसके चलते चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और वारदातें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। बीती रात भी चोरों ने नगर के गुरुद्वारा साहिब को अपना निशाना बनाया और वहां से दानपात्र जिसमें करीब 30 हजार रूपए की राशि थी, चुरा ले गए।

विधायक के घर से 10 कदम तो थाने 100 मीटर दूर हुई वारदात-रविवार सोमवार दरमियानी रात को सिख समाज के गुरुद्वारा साहिब से अज्ञात चोर दान पात्र चुरा ले गए। दान पात्र में करीब तीस हजार रूपए की राशि थी। चोरी की घटना विधायक हरदीप सिंह डंडा के घर से 10 कदम की दूरी पर और थाना परिसर से 100 मीटर की दूरी पर हुई। पुलिस थाना परिसर के नजरदीक हुई इस घटना ने नगर की पुलिस व्यवस्था की पोल खोल दी है। नगर में इससे पहले भी कई बड़ी चोरी और वाहन चोरी की वारदातें हुईं लेकिन पुलिस ने आज तक उनका पता नहीं लगा पाई।जिससे चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और चोरों के आगे पुलिस बेबस नजर आ रही है।

नगर की बड़ी और चर्चित इन चोरियों का भी अब तक खुलासा नहीं-
* 6 जून 24 को स्वास्थ्य विभाग के कमलेश ओझा के घर से 17 लाख के गहनों की चोरी। जिसमें 10 से 12 तोला सोना और 500 ग्राम चांदी की चोरी हुई थी।
* 6 जनवरी 25 को नगर के श्री गणेश ज्वेलर्स से तीन लाख के गहने



दिनदहाड़े चोरी कर गए।
* 4 अप्रैल 24 की शाम धानमंडी मार्ग से बैंक ऑफ़ इंडिया के कियोस्क संचालक संतोष गुप्ता से 2 लाख की लूट। इसके साथ ही अन्य कई चोरी की वारदातें हुई हैं और

आए दिन हो रही है। जो पुलिस कार्यशैली को मुंह चिढ़ा रही है।
विधायक के भाई ने कहा थाने में दिया आवेदन, थानाप्रभारी ने नकारा-विधायक के घर के सामने हुई इस चोरी ने पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिया। क्षेत्रीय विधायक हरदीपसिंह डंग के भाई प्रदीप सिंह डंड ने बताया कि गुरुद्वारा चोरी मामले में थाने में आवेदन दिया है। जिसमें दान पात्र में करीबन तीस हजार की राशि थी। वहीं थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति का कहना है कि चोरी की जानकारी मिली है लेकिन अभी तक किसी का भी आवेदन नहीं आया है और ना कोई फरियादी थाने पर पहुंचा है। हम अपने स्तर पर जांच कर चोरी का पता लगाने का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस नगर के सीसीटीवी कैमरे खंगालकर अज्ञात चोरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

राशन दुकान: अभी भी 75 हजार से ज्यादा लोगो की ई केवायसी बाकी

मंदसौर, 17 जून गुरु एक्सप्रेस। जिले में अभी भी राशन दुकानों के 75 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं की ई केवायसी नहीं हुई है। समय सीमा भी 15 जून से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। लेकिन, तकनीकी समस्या पीछा नहीं छोड़ रही। मोबाईल ऐप से ई केवायसी अभी भी नहीं हो पा रही। कई लोगों की ई केवायसी अभी भी मशीन पर शो नहीं हो रही। कुल मिलाकर तकनीकी समस्या बरकरार है तो वहीं प्रशासन को भोपाल से ईकेवायसी करवाने के लिए प्रयास करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

गांव और वार्डों में लगाए शिविर...

सरकारी राशन पर विभागीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हितग्राहियों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था बनाई जा रही है। इसके लिए सभी उपभोक्ताओं का ई-केवायसी कारया जाना है। उन्होंने यह भी बताया कि शेष हितग्राहियों की ई-केवायसी जून माह में पूर्ण कराने के लिए पूरे प्रदेश में गांव और वार्डों में शिविर लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि प्रदेश में शेष 54.8 लाख उपभोक्ताओं की भी ई-केवायसी जून में पूर्ण करने का लक्ष्य है। इसके लिए खाद्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शर्मा ने प्रदेश के सभी संभागायुक्त और कलेक्टरों को आवश्यक प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मोबाईल पर भी ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

समन्वय समिति की समीक्षा बैठक कल

मंदसौर, 17 जून गुरु एक्सप्रेस। अग्रणी जिला प्रबंधक श्री संजय कुमार द्वारा बताया गया कि जिला स्तरीय समन्वय समिति की समीक्षा बैठक कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग की अध्यक्षता में 19 जून 2025 को आयोजित होगी। समीक्षा बैठक दोपहर 3 बजे सुशासन भवन के सभा कक्ष में आयोजित होगी।

डिजिटल अटेंडेंस, 6 घंटे अनिवार्य... अब कॉलेज से गायब नहीं हो सकेंगे एमपी के प्रोफेसर, नहीं तो कटेगा वेतन

भोपाल, 17 जून गुरु एक्सप्रेस। प्रदेश भर के कॉलेजों में शिक्षकों सहित अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति ऑनलाइन अनिवार्य कर दी गई है। इसकी रिपोर्ट भी कलेक्टर को भेजी जाएगी। अगर ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगी तो वेतन में कटौती होगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के कई बार आदेश जारी कर चुका है। फिर से विभाग ने सभी कॉलेज के प्राचार्यों को आदेश जारी कर प्राध्यापकों सहित ग्रंथपाल, लाइब्रेरियन और अतिथि विद्वानों उपस्थिति सार्थक एप से लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
ऐप उपस्थिति लगाने से ही मिलेगा वेतन-यह भी स्पष्ट किया है कि ऐप से मिली उपस्थिति से विभाग वेतन जारी

करेगा। समस्या दूर दराज के कॉलेजों में आ रही हैं। जहां इंटरनेट नहीं होने पर सार्थक ऐप से उपस्थिति नहीं लग रही है। यहां तक फेस रीडिंग तक नहीं हो पा रही है। हालांकि इससे कई कॉलेजों में शिक्षकों की उपस्थिति पूरी हो रही है।
कलेक्टर को भेजी जाएगी उपस्थिति-प्राचार्य सार्थक एप के कॉलेजों के एपनालिटिकल हैशबोर्ड तैयार करेंगे। इसमें कॉलेज की आईडी से लॉगिन कर डाटा एनालिटिक्स देख सकेंगे। उसे जिले के कलेक्टर और उनके संभागीय आयुक्त को भी शिक्षकों की उपस्थिति को भेजना होगा। सभी की उपस्थिति की केलकुलेशन जिले के एम्प्लॉईज के उपस्थिति मार्क करने से किया जाएगा। इसमें प्रोफेसर सहित अन्य सभी वर्ग के अधिकारियों के आने और जाने के समय उपस्थिति लगाना होगी। इसमें सिर्फ आने का समय देने पर उनकी उपस्थिति मान्य नहीं की जाएगी।

6 घंटे होगी कॉलेजों में उपस्थिति-विभागीय आदेश के मुताबिक शिक्षक, खेल अधिकारी, लाइब्रेरियन, अतिथि विद्वान को कॉलेज में यूजीसी के नियम के तहत उपस्थित रहना होगा। यूजीसी ने नए नियम के तहत उक्त सभी की उपस्थिति (आने और जाने के बीच) का समय छह घंटे किया है। इससे अब सभी को 6 घंटे तक कॉलेजों में रुकना होगा। इससे कम समय होने पर उनको मिलने वाले वेतन में काट-छांट भी हो सकती है।
शिक्षकों के लिए पांच घंटे का समय निर्धारित-प्रांतीय एम. हाई विद्यालयीन प्राध्यापकसंघ अध्यक्ष आनंद शर्मा ने कहा कि शासन का आदेश शिक्षकों के लिए पांच घंटे का समय निर्धारित है। अब यूजीसी के अनुसार समय निर्धारण से अधिक घंटे पर वेतन भी मिलना चाहिए। अगर शिक्षक सभी काम से अधिक घंटे रुकते हैं तो अतिरिक्त उपस्थिति मान्य नहीं की जाएगी।

कार्यालय सम्पदा प्रबंधक
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल मंदसौर
नामान्तरण -सूचना
मण्डल की आवासीय कॉलोनी कम्बल केन्द्र मंदसौर स्थित भवन क्रमांक 1 / 4 जो श्री जयप्रकाश जायसवाल पिता श्री अम्बालाल जायसवाल को आवंटित किया गया था। उक्त भवन का विक्रय विलेख दिनांक 09.01.1978 इनके पक्ष में पंजीबद्ध करवाया गया था। इनके द्वारा उक्त भवन का विक्रय श्रीमती शकुन्तला बाई पति श्री हरिबाबु जायसवाल को कर विक्रय पत्र दिनांक 01.05.1978 को इनके पक्ष में पंजीयन निष्पादित करवाया गया था। श्रीमती शकुन्तला बाई पति श्री हरिबाबु जायसवाल का स्वर्गवास दिनांक 20.06.2024 एवं इनके पति श्री हरिबाबु जायसवाल पिता श्री अम्बालाल जायसवाल का स्वर्गवास दिनांक 05.11.2023 को हो जाने से इनके पुत्र श्री रवि जायसवाल पिता स्व. श्री हरिबाबु जायसवाल पंजीकृत वसीयत एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उक्त भवन का नामांतरण अपने नाम करवाना चाहते हैं।
अतः इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/परिवार के सदस्य/वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति/उर्ज हो तो वह विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस में मय ठोस प्रमाण के कार्यालय में प्रस्तुत करे समयावधि व्यतीत हो जाने पर उक्त भवन का नामान्तरण श्री रवि जायसवाल पिता स्व. श्री हरिबाबु जायसवाल के नाम कर दिया जावेगा उसके पश्चात कोई भी दावा/आपत्ति/उर्ज मान्य नहीं होगी।
(रिपुदमन सिंह चंद्रावत)सम्पदा प्रबंधक
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल मंदसौर (मप्र)